नईदुनिया

मुख्यमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर बेतवा नदी के उद्गम स्थल झिरी बहेड़ा से किया जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ

चार हजार करोड़ की लागत से होंगे जल संरक्षण के 990 कार्य: डॉ. यादव

भोपाल (काप्र)।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में माना गया है कि पृथ्वी पर्वत नदी पेड़-पौधों में जीवंतता है और वे हमारे लिए पूज्यनीय हैं। जिस प्रकार मानव देह में धमनियों के माध्यम से रक्त का संचार होता है उसी प्रकार नदियां पृथ्वी पर जीवन का संचार करती हैं।

अत: हम सबके लिए नदियों का अक्षुण्ण निरंतर प्रवाह आवश्यक है। नदियों के प्रवाह को दूषित करना या उनमें अवरोध उत्पन्न करना जीवन में अवरोध उत्पन्न करने के समान है। इस दृष्टि से जल स्रोतों का संरक्षण मानव जीवन के लिए आवश्यक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव विश्व पर्यावरण दिवस पर रायसेन जिले में झिरी बहेडा स्थित बेतवा नदी के उद्गम स्थल पर जल गंगा संवर्धन अभियान के शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बेतवा नदी के उद्गम स्थल की पूजा-अर्चना कर तथा बरगद का पौधा रोपकर जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया। अभियान का समापन 16 जून को गंगा दशहरे के अवसर पर उज्जैन में होगा।

किया गया 108 पौधों का रोपण

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बेतवा नदी का उद्गम राजधानी के पास से ही होता है और यहां का जल गंगा बेसिन में मिलता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों के साथ कलश यात्रा निकालकर स्थानीय महिलाओं ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के साथ जनजातीय भाई-बहनों ने 108 पौधों का रोपण किया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, पूर्व मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, विधायक सुरेन्द्र पटवा इस अवसर पर उपस्थित थे।

प्रत्येक जिले विकासखंड और पंचायत स्तर पर होंगी गतिविधियां: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्राकृतिक संसाधन ईश्वरीय देन हैं। इनकी महत्ता को स्वीकारने और उसके संरक्षण के लिए निरंतर प्रयासरत रहने के उद्देश्य से ही प्रतिवर्ष पाँच जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की परम्परा आरंभ हुई। पौधों में प्राण होते हैं इस तथ्य को सिद्ध करने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने कहा था कि भारतीय संस्कृति पौधों को जीवंत ही मानती है और उसी संवेदनशीलता के साथ उन्हें पूज्यनीय माना जाता है। डॉ. यादव ने कहा कि अभियान के अंतर्गत 3 हजार 90 करोड़ लागत के जल संरक्षण के 990 कार्य आज से प्रदेश में आरंभ हो रहे हैं। प्रत्येक जिले, विकासखंड और पंचायत स्तर पर जल संरचनाओं की मरम्मत, पर्यावरण संरक्षण और पौधरोपण के लिए जनभागीदारी से गतिविधियां संचालित की जाएंगी।

नदी जोड़ो अभियान में प्रदेश को लाभान्वित करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार: डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नदियों के संरक्षण के लिए नमामि गंगे अभियान आरंभ किया। इसी प्रकार उनकी पहल पर केन-बेतवा-लिंक परियोजना के लिए 45 हजार करोड़ रूपए मध्यप्रदेश को तथा 45 हजार करोड़ रूपए उत्तरप्रदेश को उपलब्ध करवाए गए। नदी जोड़ो अभियान की इस महती पहल से बुंदेलखंड का संपूर्ण क्षेत्र सिचिंत होगा और क्षेत्रवासियों की पेयजल संबंधी समस्या का भी समाधान होगा। इसी प्रकार राजस्थान के साथ पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो अभियान के लिए मध्यप्रदेश में 35 हजार करोड़ और राजस्थान में 35 हजार करोड़ रूपए से गतिविधियां संचालित की जाएंगी। श्री मोदी की इस पहल के लिए हम सब उनके आभारी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारे प्रदेश में कई नदियों के उद्गम स्थल हैं जो जीवन के स्त्रोत के समान महत्वपूर्ण हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत नदियों के उद्गम स्थलों के संरक्षण के लिए कार्यक्रम निरंतर जारी रहेंगे। अभियान के अंतर्गत जल संरचनाओं के प्रति जनजागृति और जल सम्मेलन जैसी गतिविधियां भी संचालित की जाएंगी।

नदियों के उद्गम स्थल पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना जरूरी: पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने जल गंगा संवर्धन अभियान आरंभ करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आभार मानते हुए कहा कि यह आवश्यक है कि अभियान को रस्म अदायगी न माना जाए। हम सभी जल स्त्रोतों को सहेजने उनकी साफ-सफाई और उनके आस-पास वृक्षारोपण जैसी गतिविधियां जनभागीदारी से सुनिश्चित करें। श्री पटेल ने कहा कि वे 16 जून तक चलने वाले अभियान में प्रत्येक दिन एक नदी के उद्गम स्थल पर जाकर स्थल के संरक्षण साफ-सफाई और वृक्षारोपण गतिविधियों में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि नदियों के उद्गम स्थल के आसपास बहेड़ा, हर्र, आम, बांस, नीम, बेल आदि के पौधे जल स्त्रोतों को संरक्षित करने और उन्हें समर्थ बनाने में सक्षम हैं अत: इस प्रकार के पौधों के रोपण को प्राथमिकता दी जाए। कार्यक्रम को विधायक सुरेन्द्र पटवा ने भी संबोधित किया।

राज्यपाल ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लगाया पौधा

भोपाल (काप्र)। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने विश्व पर्यावरण दिवस पर राजभवन के अधिकारी आवास परिसर में सागौन का पौधा लगाया। उन्होंने राजभवन में सागौन पौधरोपण का शुभारम्भ किया। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल की पहल पर राजभवन में सागौन के सौ पौधों के रोपण का कार्य किया जाएगा।

पौधरोपण के साथ वृक्ष बनने तक देखभाल का संकल्प लें : टेटवाल

भोपाल (काप्र)।

कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री गौतम टेटवाल ने राजधानी की निजामुद्दीन कॉलोनी स्थित संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क परिसर में संत शिरोमणि की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधरोपण किया।

उन्होंने कहा कि मानव के अस्तित्व के लिये पर्यावरण संरक्षण अति आवश्यक है। सभी को इस दिवस पर न केवल पौधरोपण करना चाहिये, बल्कि पौधे की वृक्ष बनने तक सम्पूर्ण देखभाल का संकल्प भी लेना चाहिये। सचिव तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार संजय गोयल, सीईओ एमपीएसएसडीईजीबी सोमेश मिश्रा एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर एमपीएसडीपी गौतम सिंह सहित उपस्थित सभी अधिकारियों ने भी पौधरोपण किया। श्री टेटवाल ने निर्माणाधीन जीएसपी की प्रयोगशाला, मीटिंग हॉल और क्लास-रूम का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि हर हाल में तय समय अवधि में निर्माण कार्य पूरा किया जाये। इस संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त बच्चा बाहर निकलकर और लोगों को भी रोजगार देने वाला बने। उल्लेखनीय है कि विश्वस्तरीय ग्लोबल स्किल पार्क में कई ट्रेड्स में बच्चों को आधुनिकतम मशीनों के माध्यम से ट्रेनिंग दी जायेगी। एक जुलाई से यहाँ प्रशिक्षण प्रारंभ हो जायेगा। यहाँ कुल 9 ट्रेड्स में बच्चे ट्रेनिंग लेंगे।

भूमि के पुनर्जीवन के लिए महत्वपूर्ण जैव ऊर्जा : तोमर

भोपाल (काप्र)।

विश्व पर्यावरण दिवस पर आज यहां एक कार्यक्रम में बोलते हुए मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भूमि के पुनर्जीवन, मरुस्थलीकरण को रोकने और सूखे से लड़ने की क्षमता विकसित करने में जैव ऊर्जा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी, क्योंकि ये संधारणीय ऊर्जा समाधान प्रदान करती है।

श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार जैविक ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कर कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के सतत एवं संतुलित विकास के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। ग्रामीण स्वयंसेवी संस्थाओं के परिसंघ (सीएनआरआई) द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में अपने मुख्य भाषण में श्री तोमर ने कहा, दुनियाभर में पर्यावरण तंत्र पर संकट की तलवार लटक रही है। जंगलों और सूखी भूमि से लेकर खेतों और झीलों तक जो मनुष्य जीवन के लिए अतिआवश्यक है, वो संकट में है। दुनियाभर में 2 बिलियन हेक्टेयर से ज्यादा भूमि खराब हो चुकी है, जोकि भारत और रूस के बराबर है। हर साल 12 मिलियन हेक्टेयर अनुमानित भूमि का स्तर खराब हो जाता है, जिसका सीधा असर वैश्विक खाद्यान्न और जल आपूर्ति पर पड़ता है। भूमि खराब होने 3.2 बिलियन लोग यानि दुनिया की 40 प्रतिशत आबादी प्रभावित होती है, जिसका सबसे ज्यादा असर ग्रामीण समुदायों, लघु किसानों और गरीबों पर पड़ता है। इस पर शीघ्रातिशीघ्र कार्य करने की आवश्यकता है।

भूमि पुनर्जीवन में एक महत्वपूर्ण चुनौती जैव ईंधन का असरदार उपयोग है, जो क्षेत्र की जैव विविधता को काफी ज्यादा प्रभावित करता है। भारत जहां विश्व की 17 प्रतिशत आबादी रहती है, वहां ऊर्जा की खपत विश्व की 5 प्रतिशत ही है। हमारी प्रति व्यक्ति ऊर्जा एवं विद्युत खपत वैश्विक औसत की एक तिहाई ही है। इसमें जैव ऊर्जा वर्ष के भूमि पुनर्जीवन, मरूस्थलीकरण को रोकने और सूखे के विरुद्ध प्रतिरोध विकसित करने के लिए ऐसे संधारित ऊर्जा समाधान उपलब्ध कराती है, जो पर्यावरण की नुकसान होने से बचाते और भूमि पुनर्जीवन प्रयासों को बल प्रदान करते हैं, उन्होंने आगे कहा।

कार्यक्रम में भाग लेते हुए इफ्को के चेयरमैन, विश्व सहकारिता आर्थिक मंच (वर्ल्ड

कोऑपरेटिव इकोनॉमिक फोरम) के संस्थापक और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (नेशनल कोआपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया - एनसीयूआई) के अध्यक्ष दिलीप संघाणी ने कहा, नई वैश्विक व्यवस्था में जलवायु परिवर्तन की बड़ी वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए सहकारी आर्थिक ढांचे को बदलना पड़ेगा। जैव-अर्थव्यवस्था की बड़ी भूमिका रहेगी, जो आजीविका समाधान प्रदान करेगी। दुनिया को एसडीजी चुनौतियों से निपटने के क्षेत्र में भारत के कार्यों से सीखने की आवश्यकता है।

ग्रामीण स्वयंसेवी संस्थाओं के परिसंघ के महासचिव बिनोद आनंद ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त किये। भूमि निम्नीकरण का परिणाम सूखा वार्षिक आधार पर 55 मिलियन लोगों को प्रभावित करता है, जो इसे पशुधन और फसलों के लिए दुनियाभर में सबसे बड़ा खतरा बनाता है। विश्व की 40 प्रतिशत आबादी यानि 3.2 बिलियन लोग भूमि निम्नीकरण से सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव संसाधन विहीन ग्रामीण समुदायों, लघु एवं सीमान्त किसानों और गरीबों पर पड़ता है। भूमि के निम्नीकरण से वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में 12त्न की कमी आती है, जिससे 2040 तक खाद्य पदार्थों की कीमतों में 30-40 प्रतिशत की उछाल का अनुमान है। इससे न केवल खाद्य सुरक्षा पर संकट है, बल्कि दुनियाभर में अर्थव्यवस्थाओं को अस्थिर कर सकता है, आनंद ने कहा।

डॉ. एस एन त्रिपाठी (आईएएस रि.), डॉ राजवीर शर्मा, डॉ पी एस बिरथल, सुश्री नील कमल दरबारी (आईएएस रि.), प्रो (डॉ) विनोद के शर्मा, विशाल सिंह, सुश्री गोपा पांडेय (आईएफएस रि.), डॉ एच पी सिंह, डॉ आर जी अग्रवाल, सीताराम गुप्ता, डॉ सुशील सिंघला (आईएफएस), विश्वास त्रिपाठी, डॉ अमिताभ कुंडू, मनीष संघाणी, नितिन चितकारा, प्रो रवि प्रकाश ओझा, जेटी चारी, डॉ राकेश अर्रावातिया, निरंजन कराड़े, प्रो मनीषा पालीवाल, राजेश लाम्बा और विपिन सैनी समेत कई गणमान्य व्यक्ति और विचारक इस अवसर पर उपस्थित रहे और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त किये।

चुनाव परिणामों को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें: अजय

भोपाल (काप्र)।पूर्व नेता प्रतिपक्ष और विधायक अजयसिंह ने प्रदेश के लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा है कि मध्यप्रदेश के लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सभी प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं ने अपनी क्षमता के अनुरूप अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में भी भरपूर मेहनत की है, फिर परिणाम चाहे जो भी हो।

श्री सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह इसका उदाहरण हैं जो लगातार अपने क्षेत्र में पैदल घूम-घूम कर मतदाताओं से आग्रह करते रहे। हमें चुनाव परिणामों को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिये। भले ही प्रदेश में अनुकूल परिणाम न आये हों, लेकिन वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और उनकी टीम की कड़ी मेहनत से कांग्रेस का उद्देश्य तो पूरा हुआ है और संविधान की रक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ऐसा संविधान जिसकी शुरुआत ही चार शब्दों यानि 'हम भारत के लोग' से हुई है। मतलब भारत के सभी लोग जिसमें सभी जातियों और धर्मों के किसान, मजदूर, युवा, व्यापारी और तमाम हुनरमंद शामिल हैं। राहुल जी की चुनावी रणनीति संविधान के इन्हीं चार शब्दों के इर्द गिर्द रही। भारत जोड़ो यात्रा इसका एक व्यापक रूप है। उन्होंने निडर होकर एक ऐसे व्यक्ति और सत्ता से मोर्चा लिया जिसे चुनौती देना बहुत कठिन काम था। एक ऐसी सत्ता जिसके साथ अपार धनबल और सरकारी एजेसियां थी। चुनाव परिणाम के बाद आज देश की जनता ने राहत की सांस ली है। राहुल गांधी की ओर यह देश आशा भरी निगाहों से देख रहा है।

लोस के बाद अब उपचुनाव की घड़ी

एक राज्यसभा और दो विस सीटों पर मुकाबला तय

भोपाल(काप्र)।

लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इन चुनावों के बाद अगले कुछ दिन तक केंद्र में नई सरकार के गठन की गहमागहमी रहेगी। इसके बाद एक बार फिर चुनाव का शोर शुरू हो सकता है। इसकी वजह यह कि इन चुनावों में मप्र से कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों से अनेक विधायक व राज्यसभा सदस्य भी चुनाव लड़े।

इनके लोकसभा में पहुंचने का असर यह होगा कि सीट रिक्त हो जाएगी, जिसके लिए उपचुनाव करवाए जाएंगे। मप्र में राज्यसभा की एक सीट के साथ विधानसभा की दो सीटों पर उपचुनाव होगा। अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर तो उपचुनाव पहले ही तय हो गया था, क्योंकि यहां पर कांग्रेस से विधायक रहे कमलेश शाह ने पार्टी और विधायकी दोनों से ही इस्तीफा दे चुके हैं। इसके अलावा एक राज्यसभा सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुना से लोकसभा चुनाव जीतने के कारण रिक्त होगी, जबकि बुदनी विधानसभा सीट शिवराज सिंह चौहान के विदिशा सीट से जीतने की वजह से खाली होगी।

केपी यादव को भाजपा भेज सकती है राज्यसभा

राज्यसभा के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का कार्यकाल 2026 तक था। अब यह सीट खाली होने से भाजपा बाकी कार्यकाल के लिए नए प्रत्याशी को राज्यसभा में भेज सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि केपी यादव को सिंधिया की जगह राज्यसभा में पहुंचने का मौका मिल सकता है। पार्टी ने गुना में केपी का टिकट काटकर ही सिंधिया को उम्मीदवार बनाया था।

बुदनी में कार्तिकेय संभाल सकते हैं विरासत

बुदनी सीट पर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा शिवराज के पुत्र कार्तिकेय सिंह को अपने पिता की विरासत संभालने का मौका दे सकती है। कार्तिकेय बुधनी क्षेत्र में काफी सक्रिय भी हैं। वहीं अमरवाड़ा सीट पर पूरी संभावना है कि भाजपा कमलेश शाह को ही अपना उम्मीदवार घोषित करेगी।

कुछ और जगह भी हो सकते हैं उपचुनाव

इसके अलावा प्रदेश में श्योपुर और बीना जैसी विधानसभा सीटें भी है, जहां से कांग्रेस के विधायक पाला बदलकर भाजपा में शामिल हो गए हैं। ये विधायक भी अगर विधायकी से इस्तीफा देते हैं, तो इन सीटों पर भी उपचुनाव की स्थिति बनेगी।

स्पेशल खबर विगत छह माह में अपराधों में आई कमी...

महिलाओं के विरुद्ध होने वाले गंभीर अपराध हुए कम

भोपाल (काप्र)।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण के संबंध में की जा रही कार्यवाहियों के अनुकूल परिणाम परिलक्षित हुए हैं।

राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो (एससीआरबी) पुलिस मुख्यालय द्वारा दिसम्बर 2023 से 15 मई 2024 तक हुए अपराधों की समीक्षा के माध्यम से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि इसी अवधि की पिछले वर्ष से तुलना करने पर न सिर्फ कुल आईपीसी अपराधों में कमी आई है बल्कि विभिन्न प्रकार के गंभीर अपराध, महिलाओं के विरुद्ध अपराध तथा अनुसुचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अपराधों में भी कमी आई है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में जीरो टोलरेंस की नीति अपनाकर त्वरित कार्यवाही की जा रही है। इसके फलस्वरूप जहां एक ओर गैंग रैप के प्रकरणों में 5.4 प्रतिशत की कमी आई है, वहीं महिलाओं के विरुद्ध घटित क्रूरता तथा दहेज प्रताडना के अपराधों में 29.6 प्रतिशत की कमी आई है। महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने के कारण ही छेडछाड के अपराधों के प्रकरणों में 11.1 प्रतिशत की कमी दृष्टिगत हुई है तथा इसी प्रकार महिलाओं के विरुद्ध कुल होने वाले अपराधों में 1.8 प्रतिशत की कमी आई है। संपत्ति संबंधी अपराधों की समीक्षा में पाया गया कि नकबजनी में 7.56 प्रतिशत की कमी आई है। इसी प्रकार सामान्य चोरी में 2.12 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई है।

पिछले छह माह में कुल 130698 आईपीसी अपराध घटित हुए। जब कि पिछले वर्ष इसी अवधि में 136650 अपराध घटित हुए हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि विगत छह माह में अपराधों में 4.36 प्रतिशत की कमी आई है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि गंभीर अपराधों जैसे हत्या के प्रकरणों में 17.31 प्रतिशत, हत्या के प्रयास में 7.21 प्रतिशत, डकैती में 53.85 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है। महिलाओं के विरुद्ध घटित गंभीर अपराधों में भी कमी आई है। बलात्कार सह हत्या के प्रकरणों में 14.3 प्रतिशत की कमी, सामूहिक बलात्कार के प्रकरणों में 5.4 प्रतिशत की कमी, बलात्कार के प्रयासों में 35.7 प्रतिशत की कमी, दहेज हत्या में 10.7 प्रतिशत की कमी, दहेज प्रताड़ना में 11.7 प्रतिशत की कमी आई है। इस अवधि में अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध घटित गंभीर अपराधों में विगत छह माहों में पिछली अवधि की तुलना में भारी कमी आई है, जैसे हत्या के प्रकरणों में गत वर्ष की तुलना में 35.3 प्रतिशत की कमी तथा हत्या के प्रयास में 20.3 प्रतिशत की कमी आई है।